सितम्बर, 1983, 24 दिसम्बर, 1983 और 23 फरवरी, 1984 को हुई । इसका पुनर्गठन हाल में 15 जुलाई, 1985 को हुआ और हाल में इसकी पहली बैठक 22 जुलाई, 1985 को हुई ।

(ख) जी नहीं । इन यंत्रों के खरीदने का कार्यक्रम राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) ने वर्ष 1985-86 के कार्यक्रम में बनाया है । उक्त विभाग ने गृह राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की अध्यक्षता में 3 वर्ष की अवधि के लिए एक अन्तर्विभागीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसका काम सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से देवनागरी एवं द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के बारे में अपनी रिपोर्ट देना है । उक्त समिति की सिफारिश पर सरकार का निर्णय प्राप्त होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी । तथापि इन उपकरणों की खरीद के बारे में राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के निदेश आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिए गए हैं और कार्यालयों ने बताया है कि आवश्यकता के अनुसार इन यंत्रों की खरीद की जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Making NCC Part of the Curriculum to all Universities and Colleges

428. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased 1o state:

(a) whether it is a fact that steps are under-way to make NCC part of the curriculum in all universities and colleges; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION ANp CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

परिवहन विकास परिषद् की सिफारिशें

429. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में दिल्ली में सम्पन्न हुई परिवहन विकास परिषद् की बैठक में ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट, वाहनों के लिये अखिल भारतीय पर्यटन परमिट, टैक्सी परमिट तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी सहयोग संबंधी विषयों पर किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : परिवहन विकास परिषद ने हाल में अक्टूबर 1985 की अपनी बैठक में सार्वजनिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिटों के सन्दर्भ में कोटा के प्रतिबन्ध को हटाने की सिफारिश की है और टैक्सियों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों की मौजूदा संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया है । बसों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों के लिए सिफारिश की गयी है कि अतिरिक्त कोटा की पहलू सहित इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये कुछ राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक छोटी समिति गठित की जाय ।

परिषद् के सदस्यों ने राजमार्ग निर्माण में निजि क्षेत्र के भाग लेने के बारे में अपने मत व्यक्त किये ।

इन्दौर-मालवा एक्सप्रेस

430. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दौर-मालवा एक्सप्रेस को कब से नियमित रूप से चलाये जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): इन्दौर-नयी दिल्ली मालवा एक्स-